भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 2590
मंगलवार, 05 अगस्त, 2025/14 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण

†2590. श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश में, सहकारी क्षेत्रों में क्षमता निर्माण हेतु सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का कार्यान्वयन कर रही है;
(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने खजुराहो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो शहर में सहकारी क्षेत्र के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया है;
(ग) यदि हाँ, तो प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) जी हाँ मान्यवर । राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त समिति है, जो सहकारी क्षेत्र में क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) एक राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है जिसमें एक राष्ट्रीय संस्थान, वैमनीकॉम (पुणे), चंडीगढ़, बेंगलुरु, गांधीनगर, पटना और कल्याणी में स्थित पांच क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (RICMs) और विभिन्न राज्यों में स्थित चौदह सहकारी प्रबंध संस्थान (ICMs)शामिल हैं। ये संस्थान सभी स्तरों पर सहकारी कर्मियों की दक्षता, शासन और पेशेवर कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम और अनुसंधान का संचालन करते हैं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद से, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) ने 13,533 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 30 जून 2025 तक देश भर में लगभग 8,31,849 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। केवल वित्तीय वर्ष 2024-25 में, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) ने 4,386 प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए और प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स), डेयरी, मात्स्यिकी और अन्य सहकारी क्षेत्रों जैसे विविध सहकारी क्षेत्रों में 3,15,382 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

(ख) और (ग): जी हाँ मान्यवर। विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण का ब्योरा इस प्रकार हैः

i) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) ने अपने एक प्रशिक्षण संस्थान, सहकारी प्रबंध संस्थान, भोपाल के माध्यम से खजुराहो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिले और खजुराहो शहर में सहकारी सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कटनी ज़िले में कुल 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 344 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया तथा पन्ना ज़िले में 5 कार्यक्रम आयोजित किए गएजिसमें 324 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया । खजुराहो शहर सहित छतरपुर जिले में 75 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) द्वारा CSC लिमिटेड के सहयोग से पैक्स सचिवों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें पैक्स को CSC पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने तथा जन औषधि केन्द्रों के संचालन पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह कार्यक्रम पन्ना जिले में आयोजित किया गया था, जहाँ 39 पैक्स सचिवों को प्रशिक्षित किया गया था, और इसके अतिरिक्त कटनी जिले के एक पैक्स सचिव को भी प्रशिक्षित किया गया था।

ii) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) ने भी पन्ना जिले सहित मध्य प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मध्य प्रदेश में आयोजित कार्यक्रमों और प्रशिक्षित प्रतिभागियों की कुल संख्या नीचे सूचीबद्ध है:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	कार्यक्रम की संख्या	मध्य प्रदेश के प्रतिभागियों की संख्या
1.	2022 – 2023	40	367
2.	2023 – 2024	50	422
3.	2024 – 2025	46	438

iii) लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान और विकास अकादमी (LINAC) और इसके 19 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (RTCs) भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और सहकारी सदस्यों को विभिन्न अनुकूलित प्रशिक्षणों के माध्यम से अधिक शिक्षाप्रद और कुशल बनाने के लिए फील्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। LINAC ने कटनी और पन्ना सहित विभिन्न जिलों को आच्छादित करते हुए मध्य प्रदेश राज्य के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान 75 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

अन्य उपायों के अलावा सरकार ने सहकारी शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक समर्पित संस्थान के रूप में "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी (TSU) हाल ही में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया है, जिसे पिछले बजट सत्र 2025 में पारित किया गया था। इस स्तर पर, विश्वविद्यालय में चार पाठ्यक्रम हैं,

जिनमें पूर्ववर्ती ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद (IRMA) का एक चल रहा पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद शुरू किए गए तीन नए पाठ्यक्रम शामिल हैं। एक संबद्ध संस्थान सहित विश्वविद्यालय में वर्तमान अनुमोदित वार्षिक प्रवेश क्षमता निम्नानुसार है:

i. डिप्लोमा कार्यक्रम: 25 सीटें
ii. स्नातक कार्यक्रम: 30 सीटें
iii. स्नातकोत्तर कार्यक्रम: 583 सीटें
iv. डॉक्टोरल कार्यक्रम: 10 सीटें

अपने संचालन के चौथे वर्ष से, विश्वविद्यालय तथा इसके संबद्ध संस्थान की संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष लगभग 9,600 स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों, लगभग 16,000 डिप्लोमा कार्यक्रमों, लगभग 60 पीएचडी. (डॉक्टोरल) कार्यक्रमों तथा लगभग 8 लाख प्रमाणपत्र कार्यक्रमों हेतु संभावित प्रवेश क्षमता होगी । त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी (TSU) की स्थापना गुजरात तक ही सीमित नहीं होगी। विश्वविद्यालय अपने स्वयं के स्कूल स्थापित करके और संबद्ध संस्थानों के माध्यम से पूरे देश में विस्तार करेगा।

प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों (MPCS) के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम: कटनी और पन्ना में नवगठित MPCSs के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जो परिचालन दक्षता, शासन और सेवा वितरण पर केंद्रित हैं।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) पर जागरूकता और प्रशिक्षण: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावा प्रक्रियाओं, जोखिम कवरेज और डिजिटल नामांकन की समझ को बेहतर बनाने के लिए पैक्स सदस्यों और सचिवों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) पर केंद्रित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं ।

3. राज्य एजेंसियों के साथ आवश्यकता-आधारित सहयोगात्मक प्रशिक्षण: राज्य सहकारिता विभाग और विभिन्न सहकारी संघों के सहयोग से, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सहकारी शासन, डिजिटल प्रणाली और वित्तीय प्रबंधन जैसे आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता ।

*****